

Manufacture of Mica Paper in India

*655. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Delegation of officials visited EEC countries in September-October last year to negotiate collaboration arrangements for the manufacture of mica paper in India;

(b) if so, what are the findings of the Delegation regarding possibilities of foreign collaboration;

(c) whether Government has decided to set up mica paper industry in the public sector; and

(d) if not, how it is proposed to implement the recommendations made by the Delegation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) A Delegation of technical officers, headed by the Chairman-cum-Managing Director, Mica Trading Corporation of India Limited (MITCO), visited selected EEC countries in September-October 1977. The Delegation was, *inter alia*, required to explore collaboration possibilities in the field of mica paper.

(b) The findings of the Delegation regarding foreign collaboration in the field of mica paper are at present being examined by MITCO.

(c) and (d). No decision to set up or otherwise a mica paper plant in the public sector has been taken.

सबू उद्योग को बंगार सामग्री पर उत्पादक शुल्क से छूट

* 656. श्री रामदेवी राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या लघु उद्योग में बनी ऋग्गार सामग्री (कास्मेटिक) पर एक वर्ष में एक

लाख रुपये तक के मान पर उत्पादन शुल्क की छूट न देने से बड़े उद्योगों के एकाधिकार को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा;

(ख) क्या लघु उद्योगों में बनी ऋग्गार सामग्री पर उत्पादन शुल्क की छूट देने से इस उद्योग को और विकास एवं विस्तार होगा जिस से रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे, तथा सरकार को और राजस्व मिलेगा ।

(ग) यदि हा, तो लघु उद्योग को यह छूट न देने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का यह निर्णय उसकी नीति के विरुद्ध नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लतीफा अन्नबाल) : (क) और (ख). सीदर्य और स्वच्छता प्रसाधनों के जिन छोटे निर्माताओं की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उन के इस किस के उत्पादन की देश में ही उपयोग के लिए, कुल निकामिया 15 लाख रुपये (मार्च, 1968 को छोड़ कर, 1977-78 के सम्बन्ध में 13.75 लाख रुपये) से अधिक की नहीं थी, उन की एक वित्तीय वर्ष में उक्त मास की 5 लाख रुपये तक के मूल्य की प्रथम विकासयो पर सरकार ने राहत देने का उपाय के रूप में 1-4-1978 से उत्पादन शुल्क से पूरी छूट दी है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Employees in State Bank of India and its Branches in Jammu and Kashmir

5971. SHRI MOHD SHAFI QURESHI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) total number of employees in the State Bank of India and its branches in the Jammu and Kashmir; and

(b) break up of these employees as follows:

1. State subjects;